



# INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 4; 2025; Page No. 374-379

Received: 21-04-2025

Accepted: 29-05-2025

Published: 19-07-2025

## भारतीय समुदायों के बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, खासकर अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों

<sup>1</sup>Pratima Kumari and <sup>2</sup>Dr. Rajneesh Rai

<sup>1</sup>Research Scholar, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

<sup>2</sup>Professor, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20111093>

Corresponding Author: Pratima Kumari

### सारांश

यह शोधप्रबंध भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता का गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें जातिगत पहचान, उसके ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्वरूप और समाज के विभिन्न आयामों—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक—पर उसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन दर्शाता है कि यद्यपि आधुनिकीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण और सकारात्मक कार्यवाही नीतियों (आरक्षण) ने कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, फिर भी जाति-आधारित असमानताएँ और भेदभाव समाज में गहराई से मौजूद हैं। शोध में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, विशेषताओं और बदलते स्वरूप पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि संरचनात्मक, कार्यात्मक और मानसिकता-स्तर के परिवर्तनों ने जातिगत विभाजनों को आंशिक रूप से कमजोर किया है, किन्तु पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में अध्ययन बताता है कि शिक्षा, रोजगार के अवसर, आर्थिक संसाधन और राजनीतिक भागीदारी जैसे कारक ऊपर की ओर गतिशीलता के प्रमुख निर्धारक हैं, किन्तु जातिगत पृष्ठभूमि इन अवसरों तक पहुँच को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है।

**मूलशब्द:** हाशिए, शिक्षा, समुदाय, सशक्तिकरण, सामाजिक रूप से, एनजीओ, आदि

### प्रस्तावना

जातिगत पहचान और सामाजिक गतिशीलता समकालीन भारतीय समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो इसके सामाजिक ताने-बाने, आर्थिक परिदृश्य और राजनीतिक गतिशीलता को आकार देते हैं। सामाजिक सुधार और आधुनिकीकरण के लिए किए गए ठोस प्रयासों के बावजूद, जाति की जड़ जमाई हुई व्यवस्था, अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों के साथ, भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालती रहती है। इसलिए भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने और लगातार असमानताओं को दूर करने के लिए जातिगत पहचान और सामाजिक गतिशीलता की गतिशीलता को समझना अनिवार्य है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में जाति व्यवस्था सहस्राब्दियों से सामाजिक संबंधों, व्यवसायों और संसाधनों तक पहुँच को नियंत्रित करने वाला एक मौलिक संगठन सिद्धांत रही है।

प्राचीन धर्मग्रंथों से उत्पन्न और सामाजिक स्तरीकरण की सदियों से विकसित, जाति व्यवस्था ने व्यक्तियों को जन्म के आधार पर पदानुक्रमित समूहों में वर्गीकृत किया, जिसमें प्रत्येक जाति को विशिष्ट भूमिकाएँ और कर्तव्य सौंपे गए। इस कठोर सामाजिक पदानुक्रम ने कई विशेषाधिकारों और नुकसानों को जन्म दिया, सामाजिक असमानताओं को कायम रखा और ऊपर की ओर बढ़ने के अवसरों को सीमित किया। समकालीन भारत में, जाति पहचान का महत्व बना हुआ है, हालांकि तेजी से आधुनिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण द्वारा चिह्नित एक परिवर्तित संदर्भ में। जबकि सकारात्मक कार्यवाही नीतियों जैसे कानूनी उपायों ने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जाति पहचान व्यक्तियों के जीवन के अवसरों और सामाजिक अंतःक्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है।

राजनीति, शिक्षा, रोजगार और विवाह सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाति एक प्रमुख कारक बनी हुई है, जो संसाधनों, सामाजिक नेटवर्क और उन्नति के अवसरों तक पहुँच पर प्रभाव डालती है। जातिगत पहचान और सामाजिक गतिशीलता की आपस में जुड़ी गतिशीलता समकालीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति और ऊपर की ओर गतिशीलता की संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है।

भारतीय समाज पर जाति व्यवस्था का प्रभाव गहरा और बहुआयामी रहा है। एक ओर, जाति-आधारित सामाजिक संरचनाओं ने सामाजिक सामंजस्य, सामुदायिक एकजुटता और जाति समूहों के भीतर आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है, जो सामाजिक संगठन और पहचान निर्माण के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। जाति-आधारित संघों, अनुष्ठानों और त्योहारों ने सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामूहिक एकजुटता के लिए अवसर प्रदान किए हैं, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता में योगदान करते हैं। हालाँकि, जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता, बहिष्कार और भेदभाव का स्रोत भी रही है, जो संसाधनों, अवसरों और सामाजिक गतिशीलता तक पहुँच में असमानताओं को कायम रखती है। जाति पहचान के आधार पर भेदभाव विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है, जिसमें अंतर-जातीय संपर्कों पर प्रतिबंध, शिक्षा और रोजगार में असमान व्यवहार और हाशिए पर पड़े जाति समूहों के खिलाफ हिंसा शामिल है।

### जाति व्यवस्था

भारतीय समाज की सामाजिक संरचना की विशेषता जाति नामक एक अनूठी सामाजिक संस्था है। भारतीय जाति व्यवस्था देश के भीतर सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक प्रतिबंध की व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के भीतर, समुदायों को हजारों अंतर्जातीय वंशानुगत समूहों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिन्हें जाति के रूप में जाना जाता है। जातियों को प्रसिद्ध श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जाना जाता है। कुछ व्यक्तियों, जैसे कि विदेशी, खानाबदोश, वनवासी जनजातियाँ और चांडाल को एक साथ बहिष्कृत किया गया और उन्हें अछूत माना गया। वर्ण व्यवस्था से सामाजिक स्तरीकरण के रूप में उभरी जाति व्यवस्था देश के लिए विशिष्ट थी। इसके अलावा, इसे भारतीय समाज का एक अविभाज्य पहलू माना जाता है।

दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में जाति व्यवस्था के लिए कोई संस्था नहीं है। भारत के अलावा, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जातियों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सबसे सटीक प्रमाण भारत में मौजूद हैं। जाति शब्द लैटिन शब्द कास्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध। पुर्तगाली लोगों ने भारतीय सामाजिक स्तरीकरण को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। व्यक्तियों ने यह दृष्टिकोण बनाया कि इस प्रणाली का उपयोग रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस शब्द को 1563 में गार्सिया डी ओर्टा ने भारतीय जाति व्यवस्था के लिए लागू किया था। जाति के लिए संस्कृत शब्द वर्ण है, जिसका अर्थ है रंग।

जाति व्यवस्था में कई जटिलताएँ हैं, जिसके कारण व्यक्ति इसकी सटीक परिभाषा को समझने में सक्षम नहीं हो पाया है। जाति व्यवस्था का प्रसार और विकास बहुत बड़ा है। इसे ऐसे कार्य के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे व्यक्ति या वर्ग की शक्ति या अधिकार द्वारा प्राप्त किया जाना है। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से व्यक्तियों के समूहों को संदर्भित करती है। इसे शास्त्रों द्वारा बनाया

गया है। मानदंड और मूल्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्तियों को मानदंडों और मूल्यों के संदर्भ में अच्छी तरह से जानकारी होना आवश्यक है। इन्हें एक प्रभावी और संगठित जीवन जीने की कुंजी माना जाता है।

भारतीय जाति व्यवस्था को देश के भीतर सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक प्रतिबंध की व्यवस्था के रूप में माना जाता है। समुदायों को हजारों अंतर्जातीय वंशानुगत समूहों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिन्हें जाति के रूप में जाना जाता है। जातियों को प्रसिद्ध श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जाना जाता है। जाति व्यवस्था पर शोध करते समय, मूल की कुशल समझ हासिल करना आवश्यक है। भारतीय जाति व्यवस्था को समाज के खंडीय विभाजन, पदानुक्रम, भोजन की आदतों पर प्रतिबंध, व्यावसायिक प्रतिबंध, धार्मिक अक्षमता, अंतर्विवाह, सामाजिक दूरी बनाए रखना, अस्पृश्यता और बसावट पैटर्न और शुद्धता की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया गया है।

### साहित्य समीक्षा

कपूर, राधिका. (2023) [1]. भारत में जाति व्यवस्था। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में जाति व्यवस्था की कुशल समझ हासिल करना है। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जानी जाने वाली जातियाँ शामिल हैं। इन्हें उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों के आधार पर समूहीकृत किया गया है। पूरे देश में सभी समुदायों में अस्पृश्यता की अवधारणा का पालन किया जाता है। अछूत लोग अलग-अलग व्यवसायों में लगे हुए हैं, जैसे, मृत जानवरों और पक्षियों के शवों को हटाना, सीवर की सफाई करना, इत्यादि। इन्हें अशुद्ध व्यवसाय माना जाता है, जो उच्च जातियों को अछूतों से दूरी बनाए रखने में सक्षम बनाता है। उच्च जातियों का दृष्टिकोण है कि उनकी स्थिति प्रदूषित हो जाएगी, इसलिए, उन्होंने सामाजिक दूरी बनाए रखी। शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणाओं का अभ्यास उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों के आधार पर किया जाता है। सभी जातियों से संबंधित व्यक्तियों का प्राथमिक लक्ष्य अपने समग्र जीवन स्तर को समृद्ध बनाना है। इसलिए, वे अपने काम के कर्तव्यों को सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करने और वांछित परिणाम उत्पन्न करने के लिए पूरे दिल से प्रतिबद्ध हैं। व्यक्ति नैतिकता, नैतिकता, परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा के गुणों को विकसित करने पर जोर देते हैं। इसलिए, यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि सभी जातियाँ सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। इस शोध पत्र में जिन मुख्य अवधारणाओं को ध्यान में रखा गया है, वे हैं भारत में जाति व्यवस्था को समझना, जाति व्यवस्था की विशेषताएँ और जाति व्यवस्था के फायदे और नुकसान।

बोलाज़ी, फ्लोरियन (2020) [2]. स्वतंत्रता (1947) के बाद से भारत में 1950 के दशक में कृषि सुधारों, 1970 के दशक में हरित क्रांति और 1990 के दशक में नवउदारवादी बदलाव के कारण कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। हालाँकि इन परिवर्तनों ने निस्संदेह देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जाति से जुड़े ऐतिहासिक रूप से वंचित व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों के लिए सामाजिक गतिशीलता के बेहतर अवसर किस हद तक खुले हैं। भारत में सामाजिक गतिशीलता के बड़े पैमाने पर अध्ययन अंतर-पीढ़ीगत डेटा की कमी और जाति श्रेणियों को जातियों (जन्म-निर्धारित अंतर्विवाही समूह) में विभाजित करने की असंभवता के कारण सीमित रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक गाँव पालमपुर की पूरी आबादी

के व्यक्तिगत स्तर पर अद्वितीय डेटा का उपयोग करते हुए, 1958 से 2015 तक सात बार सर्वेक्षण किया गया, इस थीसिस का उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि क्या समय के साथ सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है और क्या जाति, जाति के स्तर पर, सामाजिक स्तरीकरण के कारक के रूप में प्रबल है। हम व्यक्तियों की तीन पीढ़ियों में सामाजिक गतिशीलता के रुझानों, पैटर्न और निर्धारकों के अनुदैर्घ्य विश्लेषण को छह महीने के फील्डवर्क के दौरान किए गए 102 अर्ध-संरचित साक्षात्कारों के गुणात्मक विश्लेषण के साथ जोड़ते हैं। हमें सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कृषि वर्ग से दैनिक मैन्युअल श्रमिकों के वर्ग की ओर नीचे और क्षैतिज। उच्च वर्ग सामाजिक स्थिरता के संदर्भ में तुलनात्मक लाभ बनाए रखते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा तेजी से ऊपर की ओर गतिशीलता की संभावनाओं को बराबर करती है। हालाँकि, शिक्षा तक पहुँच आर्थिक असमानताओं और सामाजिक मूल के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर, सामाजिक गंतव्य पर जाति का प्रभाव सभी के लिए कम हो गया है, चाहे मूल वर्ग और शिक्षा का स्तर कुछ भी हो। इसके अलावा, हालाँकि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के पास वेतनभोगी वर्ग तक पहुँचने के अपेक्षाकृत कम अवसर हैं, लेकिन निचली जातियों के बीच सशक्तिकरण की धारणा उभरती है, जो पहले बड़े भूस्वामियों के प्रभुत्व में थीं। अंततः, जाति आंशिक रूप से वर्ग से अलग हो जाएगी, और शक्ति अनुष्ठान क्षेत्र से आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएगी। इस केस स्टडी से परे, थीसिस मिश्रित पद्धति का एक मूल दृष्टिकोण और गतिशीलता और अंतःक्रियाशीलता के भौतिक और व्यक्तिपरक आयामों का एक व्यापक विश्लेषण विकसित करती है।

कैन, प्रशांत. (2018) [3]. भारतीय समाज संभवतः दुनिया का सबसे अधिक स्तरीकृत और अत्यधिक समान समाज है। जाति भारत में सामाजिक वास्तविकता की सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक विशेषताओं में से एक रही है। लोग हजारों समूहों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह अपने इतिहास, उत्पत्ति, विश्वासों, सांस्कृतिक प्रथाओं, वैचारिक और राजनीतिक झुकाव के आधार पर दूसरे से भिन्न है। जाति को ध्यान में रखे बिना भारतीय समाज का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। जाति के मुद्दे का अध्ययन और चर्चा विभिन्न विषयों, दृष्टिकोणों और दृष्टिकोणों के माध्यम से शिक्षा जगत में इसके विभिन्न रूपों में की गई है। जाति का सवाल खत्म नहीं होता और सार्वजनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अलग-अलग रूपों और स्तरों पर उभरता रहता है। जाति और गतिशीलता को परिभाषित करने के किसी भी प्रयास में इस अमानवीय व्यवस्था के शिकार लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा। इस घटना को समझने और सिद्धांत बनाने के लिए दृष्टिकोणों को व्यापक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जाति और गतिशीलता को समझने के लिए औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी दोनों तरह के धर्म, संस्कृति और राज्य को शामिल करना होगा। प्रस्तुत शोधपत्र इस अवधारणा को समझने का एक प्रयास है और जाति और गतिशीलता से संबंधित कई प्रचलित बहसों और मुद्दों को छूता है।

गांगुली, मोनुश्री. (2020) [4]. सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष परिप्रेक्ष्य और कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य मूल रूप से एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों ही मानव व्यवहार को व्यवस्था द्वारा आकार दिए जाने के रूप में देखते हैं। अपने मूल में, संघर्ष सिद्धांत कहता है कि सामाजिक स्तरीकरण समाजों के लिए आवश्यक या स्वस्थ नहीं है, जबकि कार्यात्मक सिद्धांत कहता है कि यह आवश्यक है। जाति, वर्ग, नस्ल, जातीयता और लिंग कई समाजों में सामाजिक

पदानुक्रम और भेदभाव की कुछ प्रासंगिक श्रेणियाँ हैं। यह लेख भारतीय जाति व्यवस्था को देखने का प्रयास करता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग जाति से जो मतलब निकालते हैं, वह पारंपरिक साहित्य में इसके अर्थ से अलग है या लोग इसे पारंपरिक और रूढ़िवादी अर्थ मानते हैं। जाति एक जटिल घटना है और इसकी परिभाषा शब्दों में नहीं बताई जा सकती।

सिंह, ए. एट अल. (2021) [5]. भारत में आय असमानता में तेजी से वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय है। जबकि समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है, समस्या की पेचीदगियों को देखे बिना समस्या से निपटना मुश्किल लगता है। सामाजिक गतिशीलता एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो समस्या के कारण तक पहुँचने में मदद करता है और देश में दीर्घकालिक समानता लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य देश में व्यवसायिक गतिशीलता पैदा करने में सामाजिक पृष्ठभूमि और शिक्षा प्राप्ति की भूमिका की जाँच करना है। भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के 68वें दौर (2011-12) में आरसी एसोसिएशन मॉडल के विस्तारित संस्करण को लागू करके, हमने पाया कि भारत में व्यवसायिक गतिशीलता पैदा करने में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सामाजिक पृष्ठभूमि किसी व्यक्ति के व्यवसाय को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अध्ययन देश में मजबूत अंतर-पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिहीनता और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को सफलतापूर्वक उजागर करता है। इस संबंध में, देश में व्यक्तियों के विकास को सीमित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारकों को उजागर करने के लिए आगे के अध्ययनों की आवश्यकता है।

### हाशिए पर होने, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य असमानताओं के बीच संबंध

इस बात पर व्यापक सहमति है कि सामान्य रूप से स्वास्थ्य, तथा विशेष रूप से स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों से दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई हैं तथा हाशिए पर होने का संभावित स्तर लोगों के कल्याण को प्रभावित करता है। व्यक्तियों और समूहों के बीच। अध्ययनों ने सामाजिक और भौतिक नुकसान और खराब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को प्रदर्शित किया है। रोजगार, आवास और शिक्षा जैसे कारकों को स्वास्थ्य निर्धारकों के रूप में पहचाना जाता है, जो स्वास्थ्य में असमानताओं को कम कर सकते हैं।

इस बीच, गरीबी चाहे आय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जीवन स्थितियों या शैक्षिक स्तर से परिभाषित हो, खराब स्वास्थ्य का सबसे बड़ा निर्धारक माना जाता है। मानव गरीबी सिर्फ आय ही नहीं, बल्कि कई आयामों में अभाव है। औद्योगिक देशों को गरीबी की निगरानी सिर्फ आय और बेरोजगारी ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और साक्षरता जैसी बुनियादी क्षमताओं की कमी के सभी आयामों में करनी चाहिए, जो इस बात के महत्वपूर्ण कारक हैं कि कोई व्यक्ति समुदाय के जीवन में शामिल है या नहीं।"

"गरीबी में रहना मादक द्रव्यों के सेवन (तम्बाकू, शराब और अवैध ड्रग्स), अवसाद, आत्महत्या, असामाजिक व्यवहार और हिंसा, खाद्य असुरक्षा के बढ़ते जोखिम और कई तरह की शारीरिक शिकायतों की उच्च दरों से जुड़ा हुआ है। आज यूरोपीय समाजों में बड़ी संख्या में - और वास्तव में बढ़ती हुई - लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी गरीबी का सामना करने का जोखिम है। "निम्न स्तर की शिक्षा, निम्न व्यावसायिक वर्ग या निम्न स्तर की आय वाले

लोग कम उम्र में मर जाते हैं, और अपने छोटे जीवन में, सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक प्रचलन होता है"।

स्वास्थ्य में सामाजिक असमानताओं पर एक रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने निष्कर्ष निकाला है कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच स्वास्थ्य की स्थिति में व्यवस्थित अंतर हैं। "ये असमानताएँ सामाजिक रूप से उत्पन्न (और इसलिए संशोधित) और अनुचित हैं। व्यवहार में, यूरोपीय देशों में सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच स्वास्थ्य में सभी व्यवस्थित अंतर अनुचित और परिहार्य माने जा सकते हैं, और इसलिए उन्हें असमानता माना जा सकता है। अनुचितता के बारे में यह निर्णय सार्वभौमिक मानवाधिकार सिद्धांतों पर आधारित है"।

पश्चिमी समाजों में सामाजिक कल्याण पर प्रगति के बावजूद, लगभग सभी यूरोपीय देशों को अपनी आबादी के भीतर, साथ ही देशों के भीतर और देशों के बीच स्वास्थ्य में पर्याप्त असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। यूरो हेल्थ नेट की एक परियोजना में, जिसने यूरोप में स्थिति की जांच की, यह निष्कर्ष निकाला गया कि स्वास्थ्य असमानताओं को अकेले स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा नहीं बल्कि अंतर-क्षेत्रीय सहयोग और बहु-विषयक दृष्टिकोणों के साथ ही निपटाया जा सकता है: "सफल रणनीतियाँ जो देश अपना रहे हैं, उनमें अपस्ट्रीम (व्यापक निर्धारक - अंतर्निहित कारण) और डाउनस्ट्रीम दृष्टिकोण (अस्वस्थ परिस्थितियों के परिणामों को कम करने के उपाय) दोनों शामिल हैं।

अपस्ट्रीम दृष्टिकोण में मैक्रो सामाजिक-आर्थिक वातावरण को संबोधित करने के प्रयास शामिल हैं (जैसे यह सुनिश्चित करने के प्रयास कि राष्ट्रीय नीतियाँ मानव विकास को बढ़ावा दें और सामाजिक असमानताओं को कम करें)। वे शिक्षा, स्वस्थ कार्य स्थितियों, बेरोजगारी को कम करने, सामाजिक और सामुदायिक समावेशन नीतियों तक पहुंच में सुधार भी करते हैं। मध्य और अधिक डाउनस्ट्रीम उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि जीवनशैली से संबंधित कार्यक्रम (तंबाकू नियंत्रण, शराब का दुरुपयोग, पोषण, शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य) के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं समाज के अधिक कमजोर या वंचित समूहों को संबोधित करती हैं।

### हाशिए पर पड़े भारतीय समुदायों के बच्चों के लिए पाँच प्रमुख चुनौतियाँ

हाशिए पर पड़े बच्चों के समूह को ऐसे बच्चों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समाज के सबसे निचले या हाशिये पर रहते हैं। इस तरह के समूह को मुख्यधारा की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया जाता है। किसी चीज़ या व्यक्ति को समूह से बाहर धकेलने और उसे कम प्राथमिकता देने की प्रक्रिया। यह मुख्य रूप से एक सामाजिक घटना है जिसमें अल्पसंख्यक या उप-समूह को हाशिए पर रखा जाता है, और उनकी इच्छाओं और इच्छाओं को अनदेखा किया जाता है। हाशिए पर रहना एक विश्वव्यापी घटना है जो लाखों व्यक्तियों को प्रभावित करती है।

जो लोग हाशिए पर हैं, उनके पास अपने जीवन और संसाधनों पर सीमित नियंत्रण है। नतीजतन, वे समाज में योगदान देने की उनकी क्षमता सीमित है। एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है, जिसमें उनके अच्छे और सहायक संबंधों की कमी उन्हें स्थानीय जीवन में शामिल होने से रोकती है, जिससे अलगाव बढ़ता है। हाशिए पर होने के मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण स्थापित करना है जो व्यक्तियों को उत्पादक, स्वस्थ और रचनात्मक जीवन जीने की अनुमति देता है।

'विकास' शब्द का प्रयोग हमेशा व्यापक जुड़ाव को संदर्भित करने के लिए व्यापक अर्थ में किया जाता है।

दुनिया भर में लोगों का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर है, जो उन्हें विकास में योगदान करने से रोकता है। यह एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। नीतिगत स्तर पर, इस जटिल और वास्तविक मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिए। बच्चों की गरीबी, लिंग और समाज में जाति की स्थिति सभी बच्चों में मृत्यु दर और रुग्णता को बढ़ाते हैं। इन सबका असर उनके आहार, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, पर्यावरण और शिक्षा पर पड़ता है। गरीबी का बच्चों की मृत्यु दर और रुग्णता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत में, एक बालिका को पोषण युक्त भोजन तक असमान पहुँच और लिंग आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हिंसा, जिसका प्रमाण लिंगानुपात में गिरावट तथा बालिकाओं की संख्या को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग है।

ये उल्लंघन कई रूपों में होते हैं, जिनमें बाल श्रम, बाल तस्करी, व्यावसायिक यौन शोषण और कई अन्य प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार शामिल हैं। उदाहरण के लिए, भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें अनुमानित 12.6 मिलियन युवा खतरनाक नौकरियों में काम करते हैं। भारत में, बाल तस्करी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। जबकि बाल संरक्षण संबंधी चिंताओं पर व्यापक आँकड़े और जानकारी हमेशा सुलभ नहीं होती है, शोध से पता चलता है कि विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे हाशिए पर और सामाजिक रूप से बहिष्कृत आबादी से आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति, साथ ही गरीब।

- **भेदभाव:** इस तथ्य के बावजूद कि भारत को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष हो चुके हैं और उसने शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया है, देश में बच्चे जातिगत भेदभाव और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। धन असमानता। पूर्वाग्रह के कारण, माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते हैं। सभी के लिए समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए, न केवल पहुँच प्रदान करना महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि हाशिए पर रहने वाले बच्चे स्कूल में बने रहें। वंचित भारतीय समुदायों के विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को भी शिक्षा की तलाश में संरक्षित किया जाना चाहिए।
- **लैंगिक भेदभाव:** कई झुग्गी-झोपड़ियों और ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को शिक्षित करना पैसे की बर्बादी माना जाता है, क्योंकि लड़कियों को मुख्य रूप से घर पर रहने वाली पत्नी के रूप में देखा जाता है। लड़कियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं की कमी, माता-पिता के समर्थन और प्रेरणा की कमी, और लिंग-संवेदनशील सामग्रियों की कमी सभी ऐसी समस्याएँ हैं जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती हैं।
- **उच्च ड्रॉपआउट दर:** बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने के व्यापक प्रयासों के बावजूद, छह मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं, जिनमें से हर पाँच में से दो प्राथमिक विद्यालय पूरा करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये आँकड़े कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए काफी ज्यादा हैं। स्कूलों में भेदभाव और अपर्याप्त सुविधाओं के कारण ऐतिहासिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से वंचित समूहों में कम सीखने के परिणाम आम हैं। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता है जो समावेशी शिक्षण दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करता है और सभी पृष्ठभूमि के छात्रों की

- अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके बीच स्वस्थ बातचीत भी सुनिश्चित करता है
- **बहुभाषी विविधता:** निम्न आय वाले परिवारों के कई बच्चों को अपनी मूल भाषा या प्राथमिक भाषा में मुद्रित पठन सामग्री तक पहुँच नहीं है। भाषाई विविधता का महत्व, जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को परिभाषित करता है, कभी-कभी स्कूलों में अनदेखा कर दिया जाता है। बहुभाषी पठन और लेखन संस्कृति पर प्रभाव डालना महत्वपूर्ण है। आठ से अधिक ऐसे विद्यालय हैं कई स्थानों पर बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएँ और बोलियाँ, जो कक्षा में प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती हैं।
  - **व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव:** यह अक्सर देखा गया है कि भारत की शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। नतीजतन, माता-पिता द्वारा शिक्षा को अप्रासंगिक 'किताबी शिक्षा' के रूप में देखा जाता है, जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द जीविकोपार्जन कर सकें। यह उन कई कारणों में से एक है जिसकी वजह से भारत में स्कूल छोड़ने की दर लगातार ऊँची बनी हुई है।

### अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति

विकसित देशों सहित अधिकांश समाजों में कुछ समूहों या वर्गों का हाशिए पर होना पाया जाता है और शायद यह अविकसित देशों में अधिक स्पष्ट है। भारतीय संदर्भ में, जाति को व्यापक रूप से सामाजिक-आर्थिक स्थिति और गरीबी के प्रतिनिधि के रूप में माना जा सकता है। गरीबों की पहचान में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कुछ मामलों में अन्य पिछड़ी जातियों को सामाजिक रूप से वंचित समूहों के रूप में माना जाता है और ऐसे समूहों के प्रतिकूल परिस्थितियों और गरीबी में रहने की अधिक संभावना होती है।

ऐसे समूहों की स्वास्थ्य स्थिति और उपयोग पैटर्न उनके सामाजिक बहिष्कार का संकेत देते हैं और साथ ही गरीबी और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का भी अंदाजा देते हैं। भारतीय समाज में जाति सामाजिक असमानता का एक विशेष रूप है जिसमें अनुष्ठान शुद्धता के संदर्भ में क्रमबद्ध समूहों का एक पदानुक्रम शामिल है, जहाँ एक विशेष समूह या स्तर से संबंधित सदस्य सामान्य हित और एक सामान्य पहचान के बारे में कुछ जागरूकता साझा करते हैं। संरचनात्मक रूप से निचली जातियाँ अस्तित्व के लिए आर्थिक रूप से उच्च जातियों पर निर्भर थीं।

अनुसूचित जाति (निम्न जातियाँ) आर्थिक रूप से आश्रित, राजनीतिक रूप से शक्तिहीन और सांस्कृतिक रूप से उच्च जाति के अधीन रहीं। निम्न जातियों पर उच्च जातियों का इस तरह का प्रभुत्व उनकी समग्र जीवनशैली और भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुँच को प्रभावित करता है। भारत जैसे जाति-प्रधान देश में, दलित जो भारतीय आबादी के छठे हिस्से (लगभग 160 मिलियन) से अधिक हैं, एक ऐसे समुदाय के रूप में खड़े हैं जिनके मानवाधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया गया है। इन समूहों के खिलाफ संरचनात्मक भेदभाव शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के रूप में होता है जिसे सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था से वैधता मिलती है।

गांवों में उनकी बस्तियों का भौतिक पृथक्करण आम बात है, जिसके कारण उन्हें सबसे अस्वास्थ्यकर और रहने योग्य परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये सभी कारक उनकी स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और प्राप्त

स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। दलितों के बीच सफाईकर्म समुदाय स्वास्थ्य सेवा तक कम पहुँच के कारण तनाव और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में दलित बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले बहिष्कार और भेदभाव की प्रकृति पर अध्ययन बहुत सीमित हैं; हालाँकि, अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों में परिलक्षित होते हैं।

उदाहरण के लिए, मृत्यु दर स्वास्थ्य की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और भारत में यह देखा गया है कि दलित बच्चों के लिए शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 में 88) 'अन्य' सामाजिक समूह (प्रति 1000 में 69) के बच्चों की तुलना में अधिक है। संरचनात्मक भेदभाव सीधे तौर पर बहिष्कार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच को बाधित करता है। इन समूहों के प्रति स्वास्थ्य पेशेवरों का नकारात्मक रवैया भी स्वास्थ्य प्रणाली से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में बाधा के रूप में कार्य करता है। अनुसूचित जातियों की तरह अनुसूचित जनजातियों को भी भारतीय समाज में संरचनात्मक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

अनुसूचित जातियों के विपरीत, अनुसूचित जनजातियाँ जातीयता के आधार पर हाशिए पर धकेले जाने का परिणाम हैं। बीवी बाबू और वाईएस कुसुमा ने उल्लेख किया है कि भारत की आबादी में आदिवासी लगभग 8 प्रतिशत हैं और वे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान में फैले हुए हैं। भारत में आदिवासी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे कुपोषण से संबंधित बीमारियाँ, मलेरिया, दस्त, श्वसन संबंधी विकार आदि सहित परजीवी रोग और सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, एसटीडी और एचआईवी/एड्स आदि सहित आनुवंशिक विकार। भारत में आदिवासी कृषि मजदूरों, आकस्मिक मजदूरों, बागान मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि का एक बड़ा हिस्सा हैं।

इसके परिणामस्वरूप उनमें गरीबी, शिक्षा का निम्न स्तर, खराब स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में कमी आई है। वे समाज के सबसे गरीब तबके से हैं और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हैं। रुग्णता, मृत्यु दर और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों के आंकड़ों से पता चलता है कि आदिवासी आबादी की स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब है। ऐसे कई अध्ययन हैं जो संकेत देते हैं कि भारत में आदिवासी आबादी में संचारी रोग, आनुवंशिक विकार और पोषण संबंधी विकार अधिक प्रचलित हैं।

### निष्कर्ष

यह शोध प्रबंध भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता पर इसके परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह तर्क देता है कि जाति व्यवस्था, शुद्धता और श्रेष्ठता और हीनता की अपनी धारणाओं के साथ, भारतीय समाज में पूर्वाग्रह, भेदभाव और सामाजिक विभाजन का कारण बनी है। इन विभाजनों ने जनसंख्या के कुछ वर्गों में गरीबी, अशिक्षा और अस्पृश्यता जैसी विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है। उत्तरदाताओं के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को सारांशित करने के लिए, यह पाया गया है कि हमारे उत्तरदाताओं में से अधिकांश 30-59 वर्ष की आयु वर्ग में पाए गए। केवल कुछ ही 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में पाए गए।

हमारे अधिकांश उत्तरदाता पुरुष थे। अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता एकल परिवारों से आए थे और केवल लगभग 40% संयुक्त परिवारों से आए थे। हमारे अधिकांश उत्तरदाता

विवाहित थे। केवल कुछ ही अविवाहित या विधवा/विधुर थे। आवास की स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तरदाताओं की आवास की स्थिति इस मायने में संतोषजनक थी कि उनमें से एक बड़ा हिस्सा पक्के घरों में रह रहा था। पक्के घरों वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक था।

उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्तरों में महत्वपूर्ण सहसंबंध है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उच्च स्तर की शिक्षा वाले अनुसूचित जाति के लोग उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्राप्त करेंगे और इसके विपरीत। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शैक्षिक स्तर और सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण सहसंबंध है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शैक्षिक स्तर का सामाजिक गतिशीलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह पाया गया है कि शैक्षिक स्तर और अंतर-जातीय संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध मौजूद है और अन्वेषक ने निष्कर्ष निकाला है कि शैक्षिक स्तर और अंतर-जातीय संबंध अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं।

### संदर्भ

1. कपूर, राधिका. भारत में जाति व्यवस्था, 2023.
2. बोलाज़ी फ्लोरियन. जाति, वर्ग और सामाजिक गतिशीलता: उत्तर भारतीय गाँव में 1958-2015 का एक अनुदैर्घ्य अध्ययन।, 2020.
3. कैन प्रशांत. भारत में जाति और सामाजिक गतिशीलता: वैचारिक और सैद्धांतिक विचार. 2018;LVXIX:8-11.
4. गांगुली मोनुश्री. भारतीय जाति व्यवस्था का विश्लेषण, 2020. 10.13140/RG.2.2.24372.94087.
5. सिंह ए, फोर्सिना ए, मुनियूर के. भारत में सामाजिक गतिशीलता।, 2021. 10.48550/arXiv.2102.00447.
6. नारायण, नवीन. भारत में स्वास्थ्य सेवा में जातिवाद को बढ़ावा देना. CASTE / सामाजिक बहिष्कार पर एक वैश्विक जर्नल. 2022;3:245-262. 10.26812/caste.v3i2.442.
7. गोस्वामी नीलांजना. पश्चिम बंगाल, भारत में सामाजिक पृष्ठभूमि में असमान उच्च शिक्षा प्राप्ति: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण. कॉजेंट सोशल साइंसेज. 2022, 8. 10.1080/23311886.2022.2144135.
8. लियो इरा, पाणिग्रही देबाहुति। भारत में जातिगत भेदभाव और सामाजिक परिवर्तन। जर्नल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैजिड एंड हॉस्पिटैलिटी।, 2021. 10.55529/jsrth.12.1.6।
9. एन निवेदिता। कलंकित जाति समूहों की महिलाओं में शैक्षिक गतिशीलता: उच्च उपलब्धि प्राप्त मध्यम वर्ग की दलित महिलाओं का एक अध्ययन। तुलना करें: तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का एक जर्नल। 2023;54:1-18. 10.1080/03057925.2023.2170171।
10. भटनागर अपूर्वा. भारत में जातियों के बीच आय की गतिशीलता: एक अनुदैर्घ्य विश्लेषण। भारतीय आर्थिक समीक्षा। 2024, 58. 10.1007/s41775-023-00207-7।

#### Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.